प्रकाशनार्थ आलेख

दोहा नहीं, छोटे किसानों को बचाओ –वन्दना शिवा

भारत सरकार ने डब्लूटीओ का समर्थन करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर 'दोहा बचाओ और विकास करो' पर एक सेमिनार 12–13 मार्च को आयोजित की। डब्लूटीओ की दोहा वार्ता कानकुन में खत्म हो गई थी और हांगकांग मंत्रिस्तरीय वार्ता से पुनः जीवित होने का प्रयास कर रही है। और भारत सरकार यह उल्टे काम कर रही है।

दुनिया के गरीब देश नाराज हैं क्योंकि डब्लूटीओ के 'व्यापारिक उदारीकरण' में ज्यादा प्रगति का मतलब लाखों लोगों के जीवन को उजाड़ना होगा और यह उस विनाश से कहीं ज्यादा होगा ज़ो डब्लूटीओ ने अब तक किया है। व्यापारिक उदारीकरण के कारण भारत की खेती में जो विकृतियां उत्पन्न हुई हैं उसके कारण डेढ़ लाख से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। बीज एकाधिकार की वजह से एक ओर तो लागत मूल्य बढ़े हैं दूसरी ओर मात्रात्मक प्रतिबन्धों की समाप्ति के कारण बाजार पहुंच ने कृषि उत्पादों के दाम गिरा दिए। भारत के छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों पर डब्लूटीओ की प्राणघाती अर्थव्यवस्था को थोपा गया है।

जी–33 (गरीब देशों का संगठन, जो डब्लूटीओ में दबाव समूह के तौर पर काम करता है) छोटे किसानों को बचाने के लिए डब्लूटीओ में किए गये वादों को लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 'स्पेशल प्रोडक्ट एन्ड स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म' को अपना साधन बनाया है। जी–33 की बैठक दिल्ली में होनी थी, लेकिन इसे जकार्ता में स्थानान्तरित कर दिया गया क्योंकि भारत सरकार बैठक को कराने के लिए तैयार नहीं थी, इसके बजाय तीसरी दुनिया विरोधी बैठक 'दोहा बचाओ' दिल्ली में बुलाई गई। ऐसे समय में जब तीसरी दुनिया की सरकारें जनता के भोजन और पानी, काम और आजीविका, दवा और स्वास्थ्य के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है, तब वैश्विक बहुराष्ट्रीय शक्त्यिाँ और उनके द्वारा नियत्रित सरकारें मिल कर दोहा बचाओ पर आम सहमति बनाने की कोशिशों में जुटी हैं।

अमेरिकी सरकार बार–बार यह दोहरा रही है कि दोहा वार्ता को आगे बढाने के लिए भारत को मुख्य भूमिका निभानी है और भारत अमेरिकी कृषि व्यापारियों और उद्योगों को बाजार मुहैया कराने के लिए आगे–आगे भाग रहा है। जैसा गेहूं, चना और शराब के निर्यात और औद्योगिक उत्पादों में करों में कमी में साफ दिखाई दे रहा है। भारत अमरीका के बीच हुआ कृषि में ज्ञान समझौता द्विपक्षीय है। इस समझौते के बोर्ड में मोनसेंटों और वालमार्ट है। अमेरिकी दबाव में भारत सरकार ने पहले से ही दोहा वार्ता किए गए वादों से भी ज्यादा लागू कर दिया है यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपिय संघ दूसरे देशों पर भी लागू दोहा लागू करने के लिए भारत सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहा बचाओ सेमिनार इसी कूटनीति का हिस्सा है।

कौन प्रायोजक है? किन लोगों को इसमें बुलाया गया, और किन बातों पर बहस की गयी? इन सब बातों पर गौर से ही दोहा बचाओ सेमिनार का आधार साफ़ नजर आने लगता है। इसमें दो गैर सरकारी संगठन हैं जो पिछले एक दशक से ही डब्लूटीओ का समर्थन कर रहे हैं। पहला तो है 'कट्स', यह डब्लूटीओ का पक्षधर है क्योंकि इसके अनुसार व्यापारिक उदारीकरण से उपभोक्त्ताओं को सस्ता भोजन मिलेगा। जबकि भारत में आज खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। व्यापारिक उदारीकरण से किसानों के लिए दाम कम और उपभोक्ताओं के लिए बढ़ते हैं।

दोहा बचाओ सेमिनार के आयोजन में लगा दूसरा एनजीओ 'आक्सफैम' तब से डब्लूटीओ का समर्थन कर रहा है जब सिएटल में जनआन्दोलनों ने डब्लूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक रोक दी थी। देश भर में किसान आंदोलन किसानों के जीवन और जीविका कि रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसा सिएटल, हांगकांग में देखा गया। तो दूसरी ओर आक्सफैम डब्लूटीओ को बचाने का काम कर रहा है और इसके पीछे तर्क यह दे रहा है कि व्यापारिक उदारीकरण तीसरी दुनिया के किसानों के हितों के लिए है। जबकि डब्लूटीओ की वजह से हजारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं तो लाखों किसानों से वैश्विक कृषि व्यापारियों के लाभ के लिए जमीनें और जीविका छीनी जा रही हैं। क्योंकि डब्लूटीओ के कृषि नियम केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ के लिए हैं।

अगर दोहा बचाओ सेमिनार किसानों के विकास को लेकर होती तो इसमें वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारत में आये कृषि संकट की बात की जाती। इसमें वक्ता के तौर पर भारतीय कृषक समाज के कृष्णबीर चौधरी, भारतीय किसान यूनियन के महेन्दसिंह टिकैत, विदर्भ जनांदोलन के किशोर तिवारी या कर्नाटक राज्य रैयत संघ के पुट्टानिया शामिल होते, शरद जोशी नहीं। जब 1994 में मार्राकेश में डब्लूटीओ समझौते पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल किले पर एक लाख किसान इकट्ठे हुए तब डब्लूटीओ के समर्थन में एकमात्र आवाज शरद जोशी की थी। आज भी वह दोहा बचाओ कहने वाले अकेले ही हैं, जबकि किसान आंदोलन छोटे किसानों को बचाने की बात कर रहे हैं।

दोहा समझौते में ट्रिप्स के पुनरीक्षण और जन स्वास्थ्य का वायदा किया गया था, जबकि 'दोहा बचाओ सेमिनार' में ट्रिप्स पर कोई बात नहीं हुई। ऐसे समय में यह गलती और भी महत्वपूर्ण है जबकि नोआर्टिस भारतीय पेटेन्ट एक्ट के उन कायदों को चुनौती दे रही है जिसमें भारतीय अथवा अंतरराष्ट्रीय नागरिकों को सस्ती जैविक दवाऐं मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। भारत विश्व की 67 फीसदी दवाएं मुहैया कराता है। दोहा बचाओ सेमिनार की ट्रिप्स पर खामोशी का मतलब 'नोआर्टिस' का समर्थन है और साथ ही सस्ती दवाओं के नागरिकों के अधिकारों को खत्म करना तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को स्थापित करना है।

इस सेमिनार के परिणामस्वरूप गरीब देशों की सरोकारों के बीच किसी लोकतान्त्रिक वार्ता का आधार तैयार नहीं होगा बल्कि एनजीओ, सरकारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सांठगांठ जरूर हो जाएगी। प्रस्तुति–मीनाक्षी अरोरा (पीएनएन)

शब्द संख्या–922

आलेख प्रकाशित होने की स्थिति में अखबार की कतरन और पारिश्रमिक राशि 'पीपुल्स न्यूज नेटवर्क' दिल्ली के पते पर भेज
पीपुल्स न्यूज नेटवर्क संपादक मंडल– अमित सेन गुप्ता, अरुण अग्रवाल, भारत डोगरा, ई पी मेनन, हर्ष डोभाल, जावेद नकवी, प्रशांत भूषण, संजर
(समाचार–विचार सर्विस) कार्यकारी सम्पादक –शिराज केसर, पीएनएन, 14 सुप्रीम एन्क्लेव, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली–91, फोन–011,22756796 ईमेल–peoplesnewsnetwork@gma